विवरण

1.4.91 और 1.4.98 तक कवर न किए गए गांवों/बसावटों की राज्य/संघवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.91 तक	1.4.98 तक
आन्ध्र प्रदेश	0	0
अरूणाचल प्रदेश	0	666
असम	88	8623
बिहार	7	2522
गोआ	0	35
गुजरात	52	1008
हरियाणा	75	60
हिमाचल प्रदेश	797	4590
जम्मू व कश्मीर	662	2618
कर्नाटक	0	1942
केरल	0	990
मध्य प्रदेश	83	6909
महाराष्ट्र	52	2985
मणिपुर	0	220
मेघालय	1015	1005
मिजोरम	0	24
नागालैंड	19	448
उड़ीसा	1101	7136
पंजाब	784	6000
राजस्थान	139	7077
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	0	0
त्रिपुरा	10	888
उत्तर प्रदेश	449	384
पं० बंगाल	0	0
अं० नि० द्वीप समूह	0	11
चंडीगढ़	0	0
दा०ना० हवेली	0	128
दमन व द्वीव	0	0
लक्षद्वीप	0	0
पांडिचेरी	0	0
कुल जोड़	5333	56269

मध्य प्रदेश में ग्रामीण शिल्पकारों के लिए लागू की गई योजनाएं

442. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण शिल्पकारों के उत्थान हेतु तैयार/लागू की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनसे उन्हें स्व-रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा सके;

(ख) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान उन्हें क्या अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) मध्य प्रदेश में उक्त योजनाओं को किस हद तक लागू किया गया है; और

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया गया और किन-किन देशों को इन वस्तुओं का निर्यात किया गया?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) यह मंत्रालय उन्नत किस्म के औजारों की ग्रामीण कारीगरों को आपूर्ति की एक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य उन्नत औजारों के प्रयोग द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे ग्रामीण कारीगरों के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा उनके उत्पादन और आय में वृद्धि करना है। इस योजना के अंतर्गत बुनकरों, दर्जियों, सुई से काम करने वालों, बीड़ी बनाने वाले, कामगारों को छोड़कर विभिन्न शिल्पों में कार्यरत परंपरागत ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार किट दिए जाते हैं, विद्युत चलित औजार किट के लिए 4,500 रु० तथा हाथ के औजार किट के लिए 2,000 रुपये की औसत लागत है। संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी द्वारा इकाई लागत निर्धारित की जाती है। औजार किट की लागत की 90% की राशि भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाती है तथा शेष 10 प्रतिशत लाभार्थी को देनी होती है।

वर्ष 1997-98 के दौरान योजना के अंतर्गत बजट आबंटन 45.00 करोड़ रुपये था जिसे 1998-99 के दौरान बढ़ाकर 60.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ग) यह योजना मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है, पिछले तीन वर्षों के दौरान जिनको औजार किट दी गई उन लाभार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	लाभार्थी (संख्या)
1996-97	13,306
1997-98	20,663
1998-99 (अक्तूबर, 98 तक)	13,989

(घ) जिन ग्रामीण कारीगरों को औजार किटों की आपूर्ति की जाती है, वे अपनी पसंद की कोई भी वस्तु बनाने और अपने उत्पादों को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इन वस्तुओं के दूसरे देशों को निर्यात से संबंधित जानकारी इस मंत्रालय द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जाती है।

Revamping of anti-poverty programmes

443. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to revamp anti-poverty programmes during the Ninth Five Year Plan;

(b) if so, the salient features of the said scheme; and

(c) the effective measures being taken or proposed to be taken for implementation of the programmes?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) to (c) The Ninth Five Year Plan is in the process of formulation. The on-going poverty alleviation programmes for self employment and wage employment being implemented in the rural areas of the country are likely to be rationalised and redesigned for continuation in the Ninth Five Year Plan. These schemes are proposed to be integrated with the various sectoral programmes as well as the area development programmes within the umbrella of the Panchayati Raj Institutions.

Implementation of remote areas development programme in States

444. SHRI C.O. POULOSE: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the total amount provided by Government to the States for effective implementation of remote areas development programme during the last three years, State-wise; and

(b) the development so far achieved, State-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) and (b) Ministry of Rural Areas and Employment is implementing various programmes for rural development. The programmes extend to various parts of the country including North Eastern States as well as other remote areas. However, there is no exclusive programme being implemented by this Ministry as "remote area development programme".

Projects sanctioned by CAPART in various states

445. SHRI C.O. POULOSE: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the number of projects sanctioned by the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) in various states during the last three years, State-wise;

(b) the names of the voluntary agencies to which assistance has been provided by CAPART during the above period, State-wise; and

(c) the amount allocated, released and utilised by the agencies?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND